RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 12 AUGUST TO 18 AUGUST 2020 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 05 ■ अंक 51 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास ओर नई शिक्षा नीति 2020 Page 2

क्या है 'आत्मनिर्भर भारत' का मतलब Page 3

आर्थिक भ्रम, लगातार जारी आर्थिक संकट और अब आत्मनिर्भरता की चाह Page 4

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के इस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज को आत्मनिर्भर भारत अभियान का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि इस बड़े राहत पैकेज से भारत में लोगों को कामकाज करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और यह कोशिश की जाएगी कि अगले कुछ सालों में भारत अपनी जरूरत की अधिकतर चीजों के लिए खुद पर निर्भर हो जाए. इस हिसाब से अभियान का नाम आत्मनिर्भर भारत अभियान रखा गया है। कोरोनावायरस के बढ़ते संकट के इस दौर में सबसे बड़ी मार किसानों पर पड़ी है। इस हिसाब से आत्मनिर्भर भारत अभियान में तीन करोड़ किसानों को 4.22 लाख करोड़ रुपये का कृषि लोन दिया गया है। इसमें 3 महीने तक उन्हें लोन वापस करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही इंटरेस्ट सब्वेंशन और तुरंत लोन चुकाने के इंसेंटिव के रूप में मिलने वाली सुविधा 31 मई 2020 तक बढ़ा दी गई है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में मोदी सरकार ने किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हाथ में अधिक पैसे पहुंचाने की कोशिश की है। सरकार ने बताया है कि मार्च और अप्रैल के बीच 86,600 करोड़ रुपये के 63 लाख लोन कृषि क्षेत्र में दिए गए हैं। इसके साथ ही सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की रिफाइनेंसिंग के लिए नाबार्ड ने 29,500 करोड़ दिए हैं। (शेष पृष्ठ 2 पर)

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास ओर नई शिक्षा नीति 2020

मोदी सरकार ने 29-7-2020 को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। करीब 34 साल बाद आई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। मेरे हिसाब से ये नई शिक्षा नीति 100ज्ञ व्यावसाय अनुलक्षी है, ओर इसमें विद्यार्थी ओर उद्योग दोनों को फायदा होगा, ऐसा कहने के पीछे मेरा पिछला अनुभव है, मैं पिछले कई सालों से कहीं कॉलेजों में

एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और प्रैक्टिकल नॉलेज की क्लासेस लेने के लिए जाता रहता हूं, मैंने अक्सर वहां पर देखा कि बच्चों को जो पढ़ाया जाता है और उद्योगों की जो जरूरत है वह एक दूसरे से कतई मेल नहीं खाते, अभी तक वही पुराना तकनीकी कॉर्स बच्चो को उनके स्नातकोत्तर अभ्यास क्रम में पढ़ाया जाता है, जिससे जब को वास्तव में नौकरी ढूंढने जाते है तब नियोक्ता कि दृष्टि में वो फिट नहीं बैठते ओर इसी वजह से उनके शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उन्हें वेतन नहीं मिलता, तब हमेशा मुझे ये लगता था कि बच्चो को आरंभिक शिक्षा के साथ ही व्यवसायलक्षी ज्ञान भी देना चाइए।

नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई समिति का नेतृत्व कर रहे डॉ. कस्तूरीरंगन ने कहा बच्चों पर से बोर्ड परीक्षा का भार कम किया जाएगा, उच्च शिक्षा के लिए भी अब सिर्फ एक नियामक होगा।पढ़ाई बीच में छूटने पर पहले की पढ़ाई बेकार नहीं होगी सबसे महत्वपूर्ण बात छठी कक्षा से ही बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल शिक्षा दी जाएगी, स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। इस से ये फायदा होगा कि शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगी ओर स्कूल में ही बच्चे को नौकरी के जरूरी प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी।

इससे बच्चो को उनके प्रारंभिक शिक्षा काल में ही व्यवसाय के अनुरूप ज्ञान प्राप्त होगा ओर इंटर्नशिप के दौरान जब वो अलग अलग औधोगिक प्रतिष्ठानों का दौरा करेंगे तब उन्हें वहां की नई नई तकनीक ओर लोगो के काम करने तरीको के बारे में अनुभव प्राप्त होगा, यह अनुभव उन्हें आगे जब वो आजीविका के लिए नौकरी करने जाएंगे तब या अपना खुद का व्यवसाय चालू करेंगे तब काफी मददगार होगा।

इसके अतिरिक्त भी इस नई शिक्षा नीति में कई तरह के स्वागत योग्य बदलाव किए गए हैं,

■स्नातक स्तर पर एक साल की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट और दो साल की पढ़ाई पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

■2030 तक प्री-प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक 100 फीसदी और उच्च शिक्षा में 50 फीसदी प्रवेश दर हासिल करने की बात कही गई है।

■शिक्षा पर सरकारी खर्च 4.43 फीसदी से बढ़ाकर जीडीपी का 6 फीसदी तक करने का लक्ष्य है।

■सबसे ज्यादा अहम बदलाव इसके फॉर्मेट में किया गया है, नई शिक्षा नीति में 10ट्2 के फार्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10ट्2 के हिसाब से चलता है लेकिन अब ये 5ट्3ट्3ट्4 के हिसाब से होगा। इसका मतलब है कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा, फिर तीसरी से पांचवीं तक दूसरा हिस्सा, छठी से आठवीं तक तीसरा हिस्सा और नौंवी से 12 तक आखिरी हिस्सा होगा।

फाउंडेशन स्टेज

पहले तीन साल बच्चे आंगनबाड़ी में प्री-स्कूलिंग शिक्षा लेंगे। फिर अगले दो साल कक्षा एक एवं दो में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इन पांच सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। मोटे तौर पर एक्टिविटी आधारित शिक्षण पर ध्यान रहेगा। इसमें तीन से आठ साल तक की आयु के बच्चे कवर होंगे। इस प्रकार पढ़ाई के पहले पांच साल का चरण पूरा होगा। अगर अभिभावक चाहे तो ये प्रारंभकाल की शिक्षा वो अपने अपने बच्चो को घर पर ही दे सकते है ओर बच्चे के 8 साल के होने पर सीधी कक्षा तीसरी में कोई भी स्कूल में दाखिला करा सकते है।

प्रीप्रेटरी स्टेज

इस चरण में कक्षा तीन से पांच तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। आठ से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा।

मिडिल स्टेज

इसमें कक्षा 6-8 की कक्षाओं की पढ़ाई होगी तथा 11-14 साल की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। जैसा की में पहले बताया, कक्षा छह से ही कौशल विकास कोर्स भी शुरू हो जाएंगे।

सेकेंडरी स्टेज

कक्षा नौ से 12 की पढ़ाई दो चरणों में होगी जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। विषयों को चुनने की आजादी भी होगी।

इसके उपरांत कुछ ओर महत्वपूर्ण बदलाव इस नई नीति में किए गए है...

■10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान होगी, बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा।

■5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई और जहां तक संभव हो सके आठवीं तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।

■ स्कूलों में बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा। उनका तीन स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेगा, दूसरा सहपाठी और तीसरा उसका शिक्षक। नेशनल एसेसमेंट सेंटर 'परख' बनाया जाएगा जो बच्चों के सीखने की क्षमता का समय-समय पर परीक्षण करेगा। सौ फीसदी नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके करीब दो करोड़ बच्चों को फिर दाखिला दिलाया जाएगा।

■नई नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट (बहु स्तरीय प्रवेश एवं निकासी) व्यवस्था लागू किया गया है। आज की व्यवस्था में अगर चार साल इंजीनियरंग पढ़ने या छह सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई उपाय नहीं होता, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में एक साल के बाद सर्टिफिकेट, दो साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। यह छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला है।

■ क्ष उच्च शिक्षा में यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई की जगह एक नियामक होगा। कॉलेजों को स्वायत्ता (ग्रेडेड ओटोनामी) देकर 15 साल में विश्वविद्यालयों से संबद्धता की प्रक्रिया को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा।

■स्कूल, कॉलेजों की फीस पर नियंत्रण के लिए तंत्र बनेगा।

■स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षा भी नई शिक्षा नीति के दायरे में होगा।

■नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाया जाएगा।

■हर जिले में कला, करियर और खेल-संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में 'बाल भवन' स्थापित किया जाएगा।

■विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। त्रि-भाषा फॉर्मूला में भी यह विकल्प शामिल होगा। इसके मुताबिक, किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी। भारत की अन्य पारंपरिक भाषाएं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे। 'एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत 6-8 ग्रेड के दौरान किसी समय 'भारत की भाषाओं पर एक आनंददायक परियोजना/गतिविधि में भाग लेना होगा। कोरियाई, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पैनिश, पुर्तगाली, रूसी भाषाओं को माध्यमिक स्तर पर पेश किया जाएगा ।

ये नई शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन किए गए है, तो इसे सफल बनाना इतना आसान नहीं होगा इसमें सभी प्रतिभागी जैसे

ब्रजेश गांधी
समाजसेवी

विद्यार्थी, अभिभावक, स्कूल - कॉलेज - यूनिवर्सिटी , सरकारी तंत्र एवं उद्योगों ओर व्यवसायों को भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। एक व्यवसाई होने के नाते में इतना बता सकता हूं कि, हम सब व्यवसाई ओर उद्योगपतियों को छठी कक्षा से चालू होने वाली बच्चो कि प्रोफेशनल और स्किल शिक्षा में अपना बड़ा सहयोग करना होगा, जिससे छोटी उम्र में ही बच्चो का लगाव इस में बढ़ेगा ओर उनके नज़रिए में बदलाव आएगा। तो आइए हम सब इस शिक्षा नीति को सफल बनाएं ओर इस तरह ही हम शिक्षा के विषय में इस नीचे के श्लोक में वक्त हुवे भाव को सफल हो बाना सकते है।

मातेव रक्षति पितेव
हिते नियुक्ते
कान्तेव चापि रमयत्यपनीय
खेदम् ॥
लक्ष्मीं तनोति वितनोति
च दिक्षु कीर्तिम्
किं किं न साधयति
कल्पलतेव विद्या ॥

अर्थातः- विद्या माता की तरह रक्षा करती है, पिता की तरह हित करती है, पत्नी की तरह थकान दूर करके मन को रिझाती है, शोभा प्राप्त कराती है, और चारों दिशाओं में कीर्ति फैलाती है. सचमुच, कल्पवृक्ष की तरह यह विद्या क्या-क्या नहीं करती है।

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे
सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा
कश्चिद् दुःखभाग्भवेत् ?
ॐ शांतिः शांतिः शांतिः

आत्मनिर्भर भारत अभियान

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इसके साथ ही राज्यों को रूरल इन्फ्राट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए 4200 करोड़ की मदद दी गई है। भारत सरकार ने बताया है कि पिछले 2 महीने के दौरान प्रवासी मजदूर और शहरी गरीब लोगों के लिए कई उपाय किए गए हैं जिससे उन्हें कोरोना के बाद के दौर में जीने में आसानी हो। इसमें प्रवासी मजदूर के रहने के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के रकम के उपयोग की इजाजत दी गई है जिससे कि उनके लिए खाने और पानी की व्यवस्था की जा सके। केंद्र सरकार ने राज्यों को रू. 11000 करोड़ दिए हैं जिससे कि वह स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड की मदद से इनके लिए काम कर सकें। अर्बन होमलेस सेंटर्स में रहने वाले लोगों के लिए दिन में तीन बार खाने की व्यवस्था की गई है. 12,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप ने तीन करोड़ मास्क और सवा लाख लीटर सेनेटाइजर बनाए हैं। इसके माध्यम से भी शहरी गरीबों को काम उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है।

आत्मनिर्भर भारत के लिए कोरोना संकट को अवसर में बदलने की जरूरत

पीएम मोदी ने भारत के आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कोरोना संकट को अवसर में बदलना होगा।

पीएम मोदी ने आयात-प्रतिस्थापन की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वोत्तर भारत बांस और जैविक उत्पाद क्लस्टर बनाकर जैविक खेती का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है। उन्होंने कहा कि बाढ़, तूफान, ओलावृष्टि जैसे संकट आते हैं और समय हमारी परीक्षा लेता है। मगर ऐसे समय उज्ज्वल भविष्य की गारंटी भी लाते हैं। कोरोनावायरस एक अवसर बन जाएगा, क्योंकि इस संकट के कारण भारत आत्मनिर्भर बनेगा। आत्मनिर्भर का पाठ घर पर शुरू होता है। समय आ गया है कि भारत आत्मनिर्भर बने। देश के हर नागरिक ने इस संकट को एक अवसर में बदलने का संकल्प लेना चाहिए। हमें भारत की विकास गाथा के लिए इसे एक प्रमुख अवसर बनाना होगा। हाल के सुधारों के कारण भारतीय किसानों को उनकी असली आजादी मिली है। वे अपनी उपज बेचने के लिए देश के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। इंडस्ट्रीज को सोचना होगा कि वे भारत को उत्पादों के शुद्ध निर्यातक में कैसे बदलेंगे। एलईडी बल्ब के उपयोग के कारण भारतवासी कुल 19,000 करोड़ रुपये की बचत कर रहे हैं। उसी के कारण कार्बन उत्सर्जन भी कम हुआ है। हमें पश्चिम बंगाल में विनिर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करना है। यह साहसिक निवेश का समय है, रूढ़िवादी फैसलों का नहीं। आत्मनिर्भार भारत के मूल में 'अत्मा-विश्वस्य भारतीय' है। हमारी इकोनॉमी यूपीआई के इस्तेमाल के चलते कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस बन गई है। पीपल-सेंट्रिक, पीपल ड्रिवन और पीपल फ्रेंडली विकास हमारे शासन का हिस्सा बन गए हैं।

सुभाष चतुर्वेदी
वरिष्ठ उद्योगपति

क्या है 'आत्मनिर्भर भारत'

सचिन बंसल
प्रधान संपादक

कोविड-19 के वैश्विक असर के बाद पुरी दुनिया में मंदी का दौर आया है। भारत देश भी इससे अछूता नही है। विश्व के सबसे बडे लोकतंत्र और अधिक आबादी वाले देश भारत में महामारी का असर तेजी से बढ रहा है। इसके साथ ही आर्थिक स्थित का कमजोर होना भी जारी है। लम्बे लॉकडाउन के बाद लोगो की आर्थिक संपन्नता कम हुई तो दूसरी और रोजगार और व्यापार की कमी भी सीमा रेखा पार कर चुकी है। ऐसे में देश में आत्मनिर्भर भारत का आव्हान किया गया है लेकिन इसे इंस्टंट रिलिफ नही कहा जा सकता है क्योकि आत्मनिर्भर भारत लांग टाइम इफेक्ट के लिए है। लेकिन इसके लिए तत्काल जागने, उठने और आगे बढने की आवश्यकता होगी। इसे हम दुसरे विश्व युद्ध के बाद जापान द्वारा अपने आप को सक्षम बनाने के लिए किए प्रयासों से जोड कर देख सकते है। कैसे एक देश ने बिना किसी सहयोग के स्वंय को तकनीकी रूप से मजबूत बनाया और भी टेक्नॉलॉजी में आगे है। इसी तरह से भारत को भी अपने लिए, अपनों के लिए और सभी के लिए मजबूत होना होगा।

आत्म निर्भर भारत के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और विश्व की भलाई और समृद्धि के लिए जो कुछ भी कर सकता है, वह करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत' का मतलब यह नहीं है कि विश्व के लिए दरवाजे बंद हो गए। इसका मतलब है कि घरेलू उत्पादों और वैश्विक सप्लाई चैन का मिश्रण।' 'इंडिया ग्लोबल वीक 2020' के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा था कि भारत आज भी दुनिया की सबसे खुली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और बहुत कम देश ऐसे हैं जो भारत जितने अवसर प्रदान करते

हैं। उन्होंने कहा, 'एक तरफ भारत जहां वैश्विक महामारी का डट कर मुकाबला कर रहा है, वहीं इसके समानांतर लोगों की सेहत की चिंता करते हुए हम अर्थव्यवस्था की सेहत पर भी अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। विश्व युवा कौशल दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने ने कहा कि युवाओं के स्किल से ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चल रहा है। जिसमें नए नए उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन, संसाधन और पूंजी की व्यवस्था अनुदान के साथ किए जाने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत निर्माण का बड़े पैमाने पर असर पड़ रहा है। मोदी ने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत पांच स्तंभों पर खड़ा होगा। इनमें पहला पिलर, इकोनॉमीः एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए । दूसरा पिलर, इंफ्रास्ट्रक्चरः एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बनें। तीसरा पिलर, हमारा सिस्टमः एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति-नीति नहीं बल्कि इक्कीसवीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर, हमारी डेमोग्राफ़ीः दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफ़ी हमारी ताक़त है. आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्चा का स्रोत है। पाँचवा पिलर, डिमांडः हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताक़त है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की ज़रूरत है। देश में डिमांड बढ़ाने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेकहोल्डर का सशक्त होना ज़रूरी है। हमारी सप्लाई चेन, हमारी आपूर्ति की उस व्यवस्था को हम मज़बूत करेंगे, जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो, हमारे मज़दूरों के पसीने की खुशबू हो।

मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर भारत तक पहुंचा देश

विकास बांगड़
उद्योगपति-समाजसेवी

पीएम मोदी की खूबी है कि वे नई-नई शब्दावली गढ़ते हैं। अब उन्होंने कोरोना संकट के दौर में देश का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करते हुए राहत पैकेज के साथ ही 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने का आह्वान किया है। हर बार जब कोई नया शब्द आता है तो लोग पुराने शब्द भूल जाते हैं। पुराने शब्द की कोई चर्चा ही नहीं करता। कई लोगों को यह समझ नहीं आता कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत में क्या अंतर है? सरकार के आर्थिक सलाहकार कहते हैं कि यह मेक इन इंडिया से आगे की चीज है।

आप इस बात से भी भ्रमित हो सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन और आत्मनिर्भर भारत में क्या अंतर है? आलोचक यह भी कह रहे हैं कि संकट के इस दौर में सरकार संरक्षणवाद को बढ़ावा दे रही है। वैसे भी यह आशंका जताई जा रही है कि कोरोना संकट के बाद अब दुनिया भर में संरक्षणवाद को बढ़ावा मिलेगा। कई लोगों को यह भी नहीं समझ आता कि एक तरफ सरकार हर सेक्टर में एफडीआई बढ़ा रही है, तो यह भला आत्मनिर्भरता को बढ़ाने वाला कैसे होगा?

लेकिन सरकार इन आलोचनाओं से बेपरवाह दिखती है. उसने कोरोना संकट को अवसर में बदलते हुए ऐसे तमाम क्रांतिकारी आर्थिक सुधार कर दिए हैं, जिनकी कॉरपोरेट जगत वर्षों से मांग कर रहा था। तो मोदी सरकार 2.0 के दो साल पूरा होने पर यानी अगले एक साल में यह पता लग जाएगा कि सरकार के इन क्रांतिकारी सुधारों से अर्थव्यवस्था को कितना सहारा मिलता है।

समर्थ भारत, सक्षम भारत आत्मनिर्भर भारत

भारत ने आपदा को, अवसर में बदल दिया

विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहां, शास्त्रों में कहा गया है-एसपंथ-यानी यही रास्ता है, आत्मनिर्भर भारत। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में आज हम एक बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा, भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है. एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात बताने का प्रयास करता हूं, जब कोरोना संकट शुरू हुआ, तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। एन-95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था, आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज़ दो लाख पीपीई और दो लाख एन 95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को, अवसर में बदल दिया। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की ये दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली हैं।

साथियों आज विश्व में आत्म निर्भर शब्द के मायने पूरी तरह बदल गए हैं। ग्लोबल वर्ल्ड में आत्मनिर्भरता की परिभाषा बदल रही है। अर्थ केंद्रित वैश्वीकरण बनाम मानव केंद्रित वैश्वीकरण की चर्चा आज ज़ोरों पर है। विश्व के सामने भारत का मूलभूत चिंतन आज आशा की किरण नज़र आता है। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वासुदेव कुटुम्बकम है. विश्व एक परिवार।

भारत जब आत्मनिर्भरता की बात करता है, तब आत्मकेंद्रित व्यवस्था की वकालत नहीं करता है। भारत की आत्मनिर्भरता में संसार के सुख, सहयोग और शांति की चिंता होती है। जो संस्कृति जय जगत में विश्वास रखती हो, जो जीव मात्र का कल्याण चाहती हो, जो पूरे विश्व को परिवार मानती हो, जो अपनी आस्था में मातृ भूमिः पुतौ अहम पृथ्वीः इसकी सोच रखती हो, जो पृथ्वी को मां मानती हो, वो संस्कृति, वो भारतभूमि जब आत्मनिर्भर बनती है तब उससे एक सुखी समृद्ध विश्व की संभावना भी सुनिश्चित होती है।भारत की प्रगति में तो हमेशा विश्व की प्रगति समाहित रही है।

भारत के लक्ष्यों का प्रभाव, भारत के कार्यों का प्रभाव विश्व कल्याण पर पड़ता ही है। जब भारत खुले में शौच से मुक्त होता है तो दुनिया की तस्वीर भी बदलती है. टीबी हो, कुपोषण हो, पोलियो हो, भारत के अभियानों का असर दुनिया पर पड़ता ही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ भारत की दुनिया को सौग़ात है।

editoria!

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बढा रहा है भारत

देश के कई सेक्टर में संरचनात्मक सुधारों की ज़रूरत है, इसमें उन्होंने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, जीएसटी, कोयला क्षेत्र, सिंचाई क्षेत्र आदि का नाम भी लिया जाता है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि कई सेक्टर में नीतियां बदलने की ज़रूरत है ताकि उनमें जान डाली जा सके और उससे निवेश आएगा और नौकरियां मिल सकेंगी। आठ क्षेत्रों में सुधारों की घोषणा की है ताकि फ़ास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट आ सके। हर मंत्रालय में एक प्रोजेक्ट डेवेलपमेंट सेल बनाने की योजना है ताकि यह जाना जा सके कि कैसे निवेश लाया जा सकता है। इसमें कोयला, खनिज पदार्थ, डिफ़ेंस विनिर्माण, एयरोस्पेस मैनेजमेंट, स्पेस सेक्टर, एटॉमिक एनर्जी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। कोयला क्षेत्र में सुधार के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि कोयला खनन में कमर्शियल गतिविधि के लिए छूट दी जाएगी ताकि सरकारी एकाधिकार खत्म हो। उन्होंने कहा कि 50,000 करोड़ खनन इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए सरकार देगी और जल्द ही 50 कोयला ब्लॉक खनन के लिए नीलामी पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों पर बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने के लिए 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सेना को जिन हथियारों की ज़रूरत है वो बाहर से मंगाए जाएंगे और उन हथियारों को नोटिफ़ाई किया जाएगा जिन्हें भारत में ही बनाया जा सकता है, साथ ही हथियारों के आयातित पुर्ज़ों को भारत में बनाने की व्यवस्था की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि जो हथियार भारत में ही ख़रीदे जा सकते हैं उनके लिए अलग से बजट की व्यवस्था की जाएगी ताकि आयात बिल कम हो। ऑर्डिनेंस फ़ैक्ट्रियों के निगमीकरण किए जाने की बात भी वित्त मंत्री ने की। उन्होंने इस बात पर ज़ोर देते हुए कहा कि इन फ़ैक्ट्रियों के निगमीकरण करने का मतलब निजीकरण नहीं है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि निगमीकरण से बेहतर हथियार बनाने और कामकाज सही से चलाने में मदद मिलेगी। साथ ही ऑर्डिनेंस फ़ैक्ट्री शेयर मार्केट में लिस्टेड की जाएगी। रक्षा निर्माण में एफ़डीआई लिमिट को 49 फ़ीसदी से बढ़ाकर 74 फ़ीसदी कर दिया जाएगा। नागर विमानन क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार के तहत तीन बड़े क़दमों की घोषणा की गई। भारतीय वायु क्षेत्र की पाबंदियों को सरल-सुगम बनाया जाएगा ताकि लोगों का समय बचे और ईंधन कम खर्च हो। इस वायु क्षेत्र के विस्तार से एक हज़ार करोड़ रुपये का लाभ होगा। छह एयरपोर्ट की पीपीपी के आधार पर नीलामी की जाएगी ताकि उन्हें बेहतर तरीक़े से विकसित किया जा सके। केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण का निजीकरण किया जाएगा। इससे बेहतर सेवा दी जा सकेंगी ताकि यह देशभर के लिए एक मॉडल बन सके। सोशल बुनियादी ढांचे में 8100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। निजी क्षेत्र की कंपनियों को इसरो के संसाधन इस्तेमाल करने का प्रावधान किया जाएगा। एटॉमिक क्षेत्र में पीपीपी के ज़रिए रिसर्च रिएक्टर में शोध को बढ़ावा दिया जाएगा।

आर्थिक भ्रम, लगातार जारी आर्थिक संकट और अब आत्मनिर्भरता की चाह

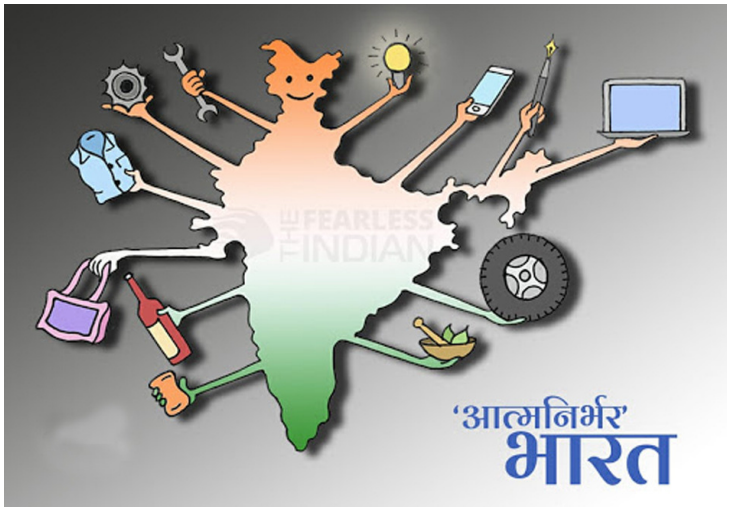

एक साल पहले जब पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार का गठन हुआ तो देश की अर्थव्यवस्था के सामने कई तरह की चुनौतियां थीं। प्रधानमंत्री मोदी जब अपने पिछले कार्यकाल के अंतिम दिनों में थे, तब से ही देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरनी शुरू हो चुकी थी। जीडीपी का आंकड़ा गिरता जा रहा था। भ्रम की स्थिति थी। उनके सत्ता में आने के बाद साल भर अर्थव्यवस्था हिचकोले खाती रही। तभी कोरोना जैसा बड़ा संकट आ गया, इस घने अंधेरे में पुराना दाग छिप गया, अब तो सामने आने वाले बड़े तूफान की ही बात हो रही है, पुरानी बात कौन करे।

मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में अर्थव्यवस्था को नोटबंदी और जीएसटी जैसे दो बड़े झटके लगे, जिसके कारण कारोबारियों में हताशा और असमंजस की स्थिति थी। लेकिन इसके बावजूद सत्ता में आने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने की बात की।

नोटबंदी और जीएसटी के झटके का असर

2017-18 के दौरान नोटबंदी और जीएसटी की दोहरी मार झेलने के बाद अर्थशास्त्रियों ने अप्रैल-जून 2018 में उपभोग आधारित हल्की उछाल आने के बाद थोड़ी सी राहत की सांस ली थी, जब जीडीपी बढ़कर 8.2 फीसदी हो गई थी। उस समय ज्यादातर आर्थिक विश्लेषकों ने यह उम्मीद जताई थी कि नोटबंदी और जीएसटी के नकारात्मक प्रभाव से अर्थव्यवस्था उबर आई है, लेकिन छह महीनों के भीतर विकास की गति तेजी से कम होने लगी।

जीडीपी के मोर्चे पर पस्त हुआ देश

वित्त वर्ष 2018 -19 में जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार सुस्त पड़ी थी. अप्रैल 2019 की तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 8.2 फीसदी थी,लेकिन अप्रैल-जून 2019 में गिरकर 6.2 फीसदी हो गई। वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी ग्रोथ महज 5 फीसदी रह गई। तो 2016-17 में देश की जो जीडीपी ग्रोथ 8.2 फीसदी थी, वह 2019-20 करीब 3 फीसदी तक घट गई। जीडीपी में गिरावट का सबसे ज्यादा चिंताजनक पहलू यह था कि उपभोग में गिरावट होने लगी थी। जनवरी-मार्च 2019 में अर्थव्यवस्था में खपत औंधे मुंह गिर रही थी- ऑटो कंपनियों की बिक्री में बिक्री में मार्च 2019 में 20 से 40 फीसदी तक की गिरावट दर्ज हुई थी। इसके पहले पांच सालों में निजी निवेश में कोई तेजी नहीं देखी गई, जो निवेश-जीडीपी अनुपात में गिरावट के आंकड़े से साफतौर पर जाहिर होता है। यही नहीं, इस संकट के दौर में लोकसभा चुनाव होने के कारण सार्वजनिक यानी सरकारी निवेश की रफ्तार भी धीमी पड़ गई।

बेरोजगारी चरम पर

रोजगार के मोर्चे पर सरकार की काफी आलोचना हो रही थी। एनएसएसओ की एक लीक रिपोर्ट में बताया गया कि 2017-18 में बेरोजगारी की दर 6.1 फीसदी तक पहुंच गई, जो 45 साल में सबसे ज्यादा है। जनवरी में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (एश्ई) की रिपोर्ट में कहा गया कि 2016 में हुई नोटबंदी और 2017 के जीएसटी रोलआउट के साइड इफेक्ट के रूप में 2018 में करीब 1.1 करोड़ नौकरियां खत्म हो गईं।

कृषि सेक्टर की हालत खराब घरेलू बचत में गिरावट

पीएम मोदी ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन कृषि सेक्टर की हालत खराब थी. कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन भी लगातार निराशाजनक रहा है। आर्थिक मोर्चे पर एक और चिंता हाल के वर्षों में घरेलू वित्तीय बचत में आई तेज गिरावट है। कम मुद्रास्फीति के बावजूद निजी खपत और निवेश धीमा हो गया है। ऑटोमोबाइल बिक्री, रेल माल, घरेलू हवाई यातायात, पेट्रोलियम उत्पादों की खपत और आयात के आंकड़े खपत में मंदी के संकेत देते हैं. प्रमुख रूप से बिकने वाले कार, दोपहिया वाहन और ट्रैक्टरों की बिक्री गिर गई।

5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात

ऐसा लगा कि पीएम मोदी इन सब चुनौतियों से विचलित होने वाले नहीं हैं। सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा। साल 2019-20 के आर्थिक सर्वे में साफ कहा गया कि देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना है. जीडीपी को फिर से 7 फीसदी तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया।

आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनमी के लिए ज़रूरी है कि जीडीपी को लगातार 8 फीसदी होना होगा। आर्थिक सर्वे के अनुसार 2018-19 मे भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 2.75 ट्रिलियन डॉलर था। तमाम जानकारों ने भी कहा कि 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को हासिल करने के लिए अगले 2-3 साल तक 8 फीसदी से ऊपर की जीडीपी ग्रोथ रेट होनी चाहिए, जिसकी दूर-दूर तक संभावना नहीं दिख रही थी।

कॉरपोरेट जगत को राहत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कंपनियों को एक बड़ी राहत देते हुए कॉरपोरेट टैक्स को कम किया और बैंकों का पुनर्गठन किया। आलोचकों ने कहा कि यह शहर केंद्रित कदम हैं जिनका उद्देश्य कॉरपोरेट निवेश को बढ़ावा देना है। मोदी सरकार कांग्रेस के मनरेगा जैसा कोई उपाय नहीं कर पाई जो ग्रामीण क्षेत्र में एफएमसीजी की खपत को बढ़ावा दे। कोरोना संकट से पहले मनरेगा को भी सरकार ने खास महत्व नहीं दिया था।

कोरोना का घना अंधेरा

अर्थव्यवस्था के सामने अब कोरोना का बड़ा तूफान, घना अंधेरा है। आलोचक तो यहां तक कहते हैं कि इसने मोदी सरकार की पुरानी खामियों पर पर्दा डाल दिया है। कोरोना ने इस गिरती अर्थव्यवस्था को और भी तबाह कर दिया है। पहले विदेशी एजेंसीज जैसे मूडीज और विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी को लेकर अनुमान जाहिर किए थे और इसे एक से दो फीसदी के आस-पास बताया था। कुछ एजेंसीज ने कहा था कि भारत की जीडीपी में नेगेटिव ग्रोथ होगी यानी गिरावट आएगी। तब भारत ने उनके अनुमानों को खारिज कर दिया था। लेकिन अब तो रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी आधिकारिक तौर पर कह दिया है कि भारत की जीडीपी निगेटिव हो सकती है। अब सभी रेटिंग एजेंसियां यह कह रही हैं कि इस वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी में 5 से 6 फीसदी की गिरावट आ सकती है।

सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज के द्वारा बाजार में मांग बनाने के लिए नकदी प्रवाह बढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन आने वाले दिनों में कम से कम एक साल तक अर्थव्यवस्था के सामने जो बड़ी चुनौती है, जिससे निबटना फिलहाल तो संभव नहीं दिख रहा है। कोरोना का असर कितना है, इसका अंदाजा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के आंकड़े से लगा सकते हैं। एश्ई का कहना है कि 3 मई को भारत में बेरोजगारी की दर देश के इतिहास में सबसे अधिक 27.11 फीसदी हो गई है। यानी कि देश का हर चौथा नागरिक बेरोजगार है।

RIL के O2C कारोबार में हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी में Aramco:अमीन नासेर

एजेंसी

Saudi Aramco के CEO अमीन नासेर ने कहा है कि RIL के oil-to-chemical (O2C) बिजनेस में 15 अरब डॉलर के निवेश के लिए Saudi Aramco ड्यूडिलीजेंस (किसी डील के पहले होने वाले वित्तीय और दूसरे जांच पड़ताल) करवा रही है। बता दें कि RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने पिछले साल अगस्त में एलान किया था कि वे RIL kesâ oil-to-chemical (O2C) बिजनेस का 20 फीसदी हिस्सा 75 अरब डॉलर की एंटरप्राइज वैल्यू पर सऊदी अरामको को बेचने की तैयारी में हैं। इस डील को इसी मार्च तक पूरा हो जाना था किंतु ये कुछ कारणों चलते अभी तक नहीं संपन्न हो पाई है।

अमीन नासेर ने निवेशकों के साथ हुई जून तिमाही अर्निंग कॉल में कहा कि अभी हम रिलायंस के साथ प्रस्तावित डील के बारे में सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इस पर due diligence की प्रक्रिया चल रही है। इस ड्यूडिलीजेंस (due diligence) के निष्कर्षों के आधार पर ही इस निवेश पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक बहुत बड़ी डील है। इस तरह का निवेश निर्णय जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता।

बता दें कि पिछले महीने हुई RIL के एजीएम में रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि Aramco के साथ होने वाली डील एनर्जी मार्केट में उत्पन्न हुई अप्रत्याशित स्थितियों और कोविड-19 महामारी की वजह से विलंबित हो गई है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस डील पर कोई काम चल रहा है या नहीं। न ही उन्होंने इस एजीएम में इस डील के लिए कोई टाइम लाइन ही बताई थी। इसी तरह सऊदी अरामको के सीईओ अमीन नासेर ने भी इस डील के पूरे होने का कोई टाइम लाइन नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि इस डील पर रिलायंस से बात जारी है और निवेशकों को इस मामले में होने वाली किसी प्रगति के बारे में सही समय पर सूचित किया जाता रहेगा। गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त में RIL के प्रमुख मुकेश अंबानी ने O2C की 20 फीसदी हिस्सेदारी सऊदी अरामको को बेचने के लिए इनीशियल एग्रीमेंट्स की घोषणा की थी।यह सौदा 15 अरब डॉलर में हो रहा है। इस सौदे में रिलायंस के सभी रिफाइनिंग व पेट्रोकेमिकल्स एसेट्स कवर होंगे।

आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज

आत्मनिर्भर भारत एप चैलेंजः विजेताओं की हुई घोषणा, Chingari को मिला बेस्ट एप का अवार्ड

नई दिल्ली। एजेंसी

चाइनीज एप्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल और आत्मनिर्भर भारत की ओर और कदम बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज (AatmaNiRhar Bharat Innovate Challenge) लॉन्च किया था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अटल इनोवेशन मिशन की साझेदारी के तहत नीति आयोग ने डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत इनोवेट चैलेंज शुरू किया है जिसके तहत आपको मोबाइल गेम्स, सोशल मीडिया और फोटो-वीडियो एडिटिंग एप बनाना होगा। इस चैलेंज के तहत अधिकतम 20 लाख रुपये तक का इनाम मिलेगा। इस चैलेंज का मंत्र है 'मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड'।

एक साथ 59 चाइनीज एप्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज का एलान किया था जिसके तहत तमाम डेवलपर्स और आईटी कंपनियों ने अपने एप को लेकर आवेदन किए थे। अब सरकार ने इस चैलेंज के विजेताओं की घोषणा की है।

चाइनीज एप्स बैन होने के बाद भारतीय शॉर्ट वीडियो एप चिंगारी (Chingari) को काफी फायदा हुआ था। रातों-रात लाखों लोगों ने इस मेड इन इंडिया एप को डाउनलोड किया। वहीं अब चिंगारी एप को एक उपलब्धि मिली है। चिंगारी एप को आत्मनिर्भर भारत एप चैलेंज में पहला इनाम मिला है। इसके

तहत कंपनी को इनाम के तौर पर सरकार की ओर से 20 लाख रुपये मिलेंगे।

इस उपलब्धि पर चिंगारी एप के को-फाउंडर और सीईओ सुमित घोष ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें आत्मनिर्भर भारत के लिए आह्वान किया जिसे अमल में लाते हुए चिंगारी की टीम इस पर लगातार काम करती रही। यह हमारे लिए गर्व का क्षण है। हमें सोशल मीडिया श्रेणी में सबसे अच्छे एप के रूप में चुना गया है।' बेस्ट सोशल मीडिया एप के लिए चुने जाने से पहले चिंगारी एप को टॉप-3 एप में चुना गया था। चिंगारी का मुकाबला मित्रों और शेयरचैट से था लेकिन ये एप फाइनल राउंड में क्वालिफाई नहीं कर पाए।

भारत में Tiktok की जगह लेगा Chingari App, 22 दिन में हुआ था एक करोड़ डाउनलोड

चाइनीज एप्स का भारत में विरोध शुरू हुआ तो सबसे पहले मित्रों (शीदह) सामने आया। बाद में मित्रों पर पाकिस्तानी कनेक्शन का आरोप लगा। कंटेंट पॉलिसी के उल्लंघन के कारण मित्रों एप को गूगल प्ले-स्टोर से हटा दिया गया, हालांकि कुछ दिन बाद गूगल प्ले-स्टोर पर एप मित्रों एप वापस आया। मित्रों एप भले ही पहले लॉन्च हुआ, लेकिन भारत में टिकटॉक को टक्कर चिंगारी (Chingari) एप ही दे रहा है। महज 22 दिन में चिंगारी एप को एक करोड़ से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया था। खास बात यह कि महज एक सप्ताह में प्ले-स्टोर पर टॉप टू फ्री एप में चिंगारी एप आ गया था। महज एक सप्ताह में चिंगारी एप को 25 लाख से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया था।

रत्न एवं आभूषण उद्योग ने मांगा 900 करोड़ रुपये का पैकेज

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

कोरोना वायरस के चलते मंदी का सामना कर रहे रत्न एवं आभूषण संवर्द्धन परिषद (जीजेईपीसी) ने केंद्र सरकार से 900 करोड़ रुपये के पैकेज की मांग की है. जीजेईपीसी ने कहा कि हम इस पैकेज का इस्तेमाल स्किल डेवलपमेंट तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष (टीयूएफ) के लिए करेंगे जिससे उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा. इससे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार पैदा होंगे. जीजेईपीसी के चेयरमैन कोलिन शाह ने बयान में कहा, ''हमारे 85 प्रतिशत यानी 5,931 सदस्य सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रम (एमएसएमई) श्रेणी के है. इनमें से ज्यादातर हस्तनिर्मित

स्वर्ण आभूषण, हीरों और कीमती रत्नों की कटिंग और पॉलिश करने का काम करते है. हमारा यह क्षेत्र श्रम आधारित और निर्यात के भरोसे है.'' शाह ने कहा कि रत्न एवं आभूषण उद्योग ने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रम (एमएसएमई) मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष वर्चुअल प्रस्तुतीकरण में 900 करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज की मांग की है. उन्होंने कहा कि इस पैकेज का इस्तेमाल 'आदर्श विनिर्माण कार्यशाला' स्थापित करने के लिए किया जाएगा, जो कौशल विकास कार्यक्रमों के अद्यतन पर केंद्रित होगी. शाह ने कहा कि टीयूएफ से एमएसएमई क्षेत्र को लाभ होगा. इससे आधुनिक प्रौद्योगिकी लगाई जा सकेगी जिससे उत्पादकता बढ़ेगी, लागत घटेगी, गुणवत्ता में सुधार होगा और नवोन्मेषण को बढ़ावा मिलेगा. इससे एमएसएमई वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सकेंगे.

आत्मनिर्भर भारत अभियान से इंडिया के साथ साथ भारत की भी होगी बल्ले बल्ले

नई दिल्ली। एजेंसी

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के लाभार्थी में देश का गरीब नागरिक, श्रमिक, प्रवासी मजदूर, पशुपालक, मछुआरे, किसान, संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र के व्यक्ति, काश्तकार, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यमवर्गीय उद्योग को पीएम मोदी राहत पैकेज के लाभ मिलेंगे। जिससे 10 करोड़ मजदूरों को लाभ होगा, एमएसएमई से जुड़े 11 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा, इंडस्ट्री से जुड़े 3.8 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचेगा और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े 4.5 करोड़ कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु-मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए है, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है। इस आर्थिक पैकेज से गरीब मजदूरों, कर्मचारियों के साथ ही होटल तथा टेक्सटाइल जैसी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को फायदा होगा।

आत्मनिर्भर भारत अभियान राहत पैकेज के अंतर्गत कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं जिनके तहत कृषि आपूर्ति श्रृंखला व प्रणाली में सुधार, सरल और स्पष्ट नियम कानून, उत्तम आधारिक संरचना, समर्थ और संकल्पित मानवाधिकार, बेहतर वित्तीय सेवा, नए व्यवसाय को प्रेरित करना, निवेश को प्रेरित करना और मेक इन इंडिया मिशन पर विशेष बल दिया जा रहा है। वास्तव में, आत्मनिर्भरता आत्मबल और आत्मविश्वास से ही संभव है। इसलिये हम सभी परस्पर मिलकर देश के विकास में योगदान दें और वैश्विक आपूर्ति चयन में अपनी भूमिका निभाएं। क्योंकि आज भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती इस आपदा के रूप में खड़ी है। भले ही हमारे पड़ोसी हमसे जलते भुनते हैं, लेकिन भारत की संस्कृति और भारत के संस्कार हमें संसार के सुख सहयोग और शांति की चिंता सिखाती है। इसलिए हमलोगों को एक दूसरे से मिलकर अपनी पूरी संकल्प शक्ति के साथ इस महामारी का सामना भी करना है और भारत को विकास की दिशा में अग्रसर करने के लिए अपना अपना अहम योगदान भी देना है।

आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत एमएसएमई क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश को नंबर वन रहना है

बैंकों के साथ नियमित मॉनिटरिंग की जाए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज 1 एवं 2 संबंधी बैठक ली

भोपाल। आईपीटी नेटवर्क

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश को नंबर वन रहना है। अभी प्रदेश में इस कार्य की गति धीमी है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश को एमएसएमई क्षेत्र में इसके अंतर्गत 21 हजार करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, वहीं मध्य प्रदेश को अभी तक लगभग 2 हजार करोड़ रुपए ही मिले हैं। संबंधित विभाग बैंकों के साथ नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर कार्य में गति लाएं।

अन्य राज्यों की प्रगति की समीक्षा करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि एमएसएमई क्षेत्र में अन्य राज्यों द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाए, जिससे यह स्पष्ट हो सके हमारे राज्य में इसकी गति धीमी क्यों है।

अनावश्यक स्टांप ड्यूटी न देनी पड़े

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कई प्रकरणों में अनावश्यक स्टांप ड्यूटी लिए जाने की बात सामने आ रही है। इस संबंध में विभाग यह सुनिश्चित करें कि हितग्राही को अनावश्यक स्टांप ड्यूटी न देनी पड़े।

केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई आ रही है अथवा यदि कोई चीज स्पष्ट नहीं है तो इसके लिए उनकी ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री को तुरंत पत्र लिखा जाए।

अब 200 करोड़ तक के लोन के लिए ग्लोबल टेंडर नहीं

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि केंद्र द्वारा घोषित पैकेज के अंतर्गत अब यह प्रावधान किया गया है कि एमएसएमई को 200 करोड़ रुपए तक के लोन के लिए अब ग्लोबल टेंडर की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने संबंधित विभाग को निर्देश दिए आगे एक सप्ताह के अंदर इस संबंध में औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं।

45 दिन के अंदर ऋण का भुगतान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पैकेज के अंतर्गत एमएसएमई उद्योग को स्वीकृत ऋण का भुगतान बैंकों द्वारा 45 दिन के अंदर किए जाने का प्रावधान किया गया है। प्रमुख सचिव ने बताया कि कुछ प्रकरण बैंकों में 45 दिन से अधिक समय से लंबित है। इस पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए को 45 दिन के अंदर ऋण की राशि का भुगतान हो जाए।

मुद्रा शिशु लोन अनुदान

आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत एमएसएमई को मुद्रा शिशु लोन अनुदान का भी प्रावधान किया गया है। प्रमुख सचिव ने बताया कि अभी इसमें प्रगति बहुत कम है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मुख्य सचिव श्री बैंस को निर्देश दिए कि वे इस संबंध में परीक्षण करें कि ऐसा क्यों है।

बैंकों का पूर्ण सहयोग आवश्यक

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि एमएसएमई क्षेत्र को नियत समयावधि में प्रावधानों के अनुसार बैंकों की ओर से ऋण प्राप्त हो जाए यह सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर बैंकों की नियमित मॉनिटरिंग की व्यवस्था हो। बैंकों के पूर्ण सहयोग से ही इस कार्य में वांछित प्रगति आ सकती है

इलेक्ट्रॉनिक में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारी की बड़ी तैयारी शुरू

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

इलेक्ट्रॉनिक सामानों में इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे जरूरी पार्ट सेमीकंडक्टर (Semiconductors) को लेकर आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत ने कमर कस ली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जापानी कंपनियों के सहयोग से देश में ही बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग (Manufacturing) की तैयारी शुरू हो चुकी है। अगले हफ्ते इससे संबंधित मंत्रालयों की DPIIT ने बुलाई है. इस हाई लेवल मीटिंग में (High Level Meeting) में मेक इन इंडिया (Make in India) के तहत निवेश के लिए स्पेशल इनसेंटिव स्कीम (Special Incentive Scheme) से लेकर Regulatory अड़चनों को दूर करने पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि मौजूदा समय में भारत 99 फीसदी सेमीकंडक्टर्स विदेशों से इंपोर्ट करता है। खासकर चीन और ताइवान से इन्हें मंगाया जाता है। Semiconductors की Manufacturing में आत्मनिर्भर बनेगा भारत- Make In India के तहत Fabrication unit लगाने के तैयारियां शुरू हो गई है। भारत सेमीकंडक्टर्स के इंपोर्ट पर सालाना 1000-1200 करोड़ डॉलर (75-90 हजार करोड़ रुपये) खर्च करता है।

समुद्र में केबल बिछाने में आत्मनिर्भर बना भारत

BSNL ने चेन्नई-पोर्ट ब्लेयर के बीच बिछाई 2300 किमी केबल

नई दिल्ली। भारत समुद्र के भीतर आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के मामले में भी आत्मनिर्भर हो गया। चेन्नई से लेकर पोर्ट ब्लेयर के बीच समुद्र के भीतर 2300 किलोमीटर केबल बिछाने का काम सरकारी कंपनी बीएसएनएल ने पूरा किया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके साथ ही अंडमान निकोबार और इसके आसपास के द्वीप वाले इलाके में सभी प्रकार की टेलीकॉम सेवा सुगम और तेज हो जाएगी। मोबाइल फोन में 4जी सेवा मिलने लगेंगी। इंटरनेट की स्पीड पहले के मुकाबले काफी तेज हो जाएगी।

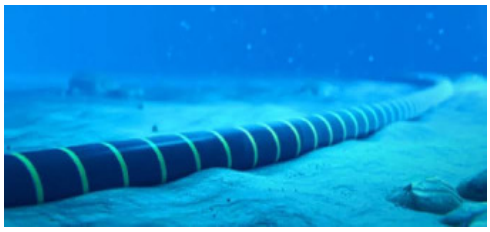

विशेषज्ञों के मुताबिक समुद्र में केबल बिछाने की सफलता से समुद्री इलाके के साथ देश की सुरक्षा में भी मदद मिलेगी। अंडमान-निकोबार इलाके में पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। कोच्चि और लक्षद्वीप के बीच भी समुद्र के भीतर आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम किया जा रहा है। टेलीकॉम विशेषज्ञों के मुताबिक समुद्र के भीतर ब्राडबैंड केबल डालने से इंटरनेट की स्पीड काफी तेज हो जाती है। भारतीय समुद्र में 30,000 किलोमीटर आप्टिकल फाइबर केबल डालने की गुंजाइश है।

पीएचडी चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री की टेलीकॉम कमेटी के चेयरमैन संदीप अग्रवाल के मुताबिक अभी समुद्र के अंदर केबल बिछाने के काम में विदेशी कंपनियों को महारत है, लेकिन अब भारत इस दिशा में आत्मनिर्भर हो गया है। उन्होंने बताया कि अभी सिंगापुर या यूरोप के साथ भारत की टेलीकॉम सेवा समुद्र में बिछाए गए केबल की बदौलत ही चलती है और इस काम में विदेशी कंपनियों का ही दबदबा है। इससे पहले बीएसएनएल ने विदेशी कंपनियों की मदद से भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री केबल बिछाने का काम किया था जिसकी लंबाई काफी छोटी थी। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के बीच समुद्री केबल बिछाने के काम में लगभग 1224 करोड़ रुपए की लागत आई है। भारत सरकार के संचार विभाग के अधीन यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) से इस परियोजना के लिए राशि दी गई।

मजबूत, सशक्त और 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए व्यापार निकाय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं: पीयूष गोयल

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि कोविड-19 ने दुनिया को बदलकर रख दिया है लेकिन भारतीय लोगों, व्यवसायों और उद्योगों ने खुद को इस संकट का शिकार नहीं होने दिया है और दृढ़ता की अनूठी विशेषता के साथ संकट का सामना किया है और स्थिति से निपटने और संकट को अवसर में तब्दील करने के लिए लगातार नए-नए तरीके विकसित किए हैं।

श्री गोयल ने भारत के उद्योगों और व्यापार निकायों की भूमिका को स्वीकार करते हुए कहा कि उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़कर काम किया है और पीपीई का उत्पादन करके, आईसीयू बेड के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करके, क्वारंटाइन सुविधाएं और मास्क विनिर्माण और अन्य पीपीई उपकरणों का उत्पादन करके भारत को कोविड की स्थिति से निपटने के लिए इस प्रकार तैयार किया है कि भारत अब पीपीई का निर्यात करने में भी सक्षम बन चुका है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, जैसा कि वस्तुओं के स्थानांतरण और बिजली की खपत में वृद्धि से संकेत मिल रहे हैं। विनिर्माण की शुरुआत परिचालन के उचित स्तर के साथ हो चुकी है। निर्यात में वृद्धि देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि कोविड से पहले और कोविड के बाद की दुनिया अलग होगी और हम कोविड के बाद बेहतर दुनिया की दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं।

श्री गोयल ने कहा कि एक देश के रूप में, भारत को कोविड के बाद की दुनिया के लिए उत्पादन में वृद्धि, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कोशिश, सुविधाजनक लॉजिस्टिक्स चैनल, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारण और अभिनव प्रथाओं का उपयोग करके निवेश, बुनियादी ढांचे और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सरकार और व्यापारिक निकायों को विकास को बढ़ावा देने, युवाओं को ज्यादा रोजगार देने, रोजगार उत्पन्न करने और दुनिया के साथ मजबूती के साथ जुड़ने के लिए साथ आना चाहिए और दुनिया के लिए दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए बल्कि 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए स्वावलंबी बनना चाहिए।

भारत अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा, सरकार ने दी मंजूरी

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

खादी अगरबत्ती 'आत्मनिर्भर मिशन' नाम के इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में बेरोजगारों और प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार पैदा करना और घरेलू अगरबत्ती उत्पादन में पर्याप्त तेजी लाना है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने अगरबत्ती उत्पादन में भारत को आत्म-निर्भर बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ख्ब्ध्य द्वारा प्रस्तावित एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्रालय ने अगरबत्ती व्यवसाय को बढ़ाने और इस क्षेत्र में आयात इम्पोर्ट घटाने हेतु बड़ा कदम उठाया है। एमएमएमई मंत्रालय ने कहा है कि 'खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन' का लक्ष्य देश में अगरबत्ती के उत्पादन में उल्लेखीय वृद्धि के साथ-साथ भारत के विभिन्न हिस्सों में बेरोजगार और प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना है। मंत्रालय ने कहा है कि इस प्रस्ताव को पिछले महीने एमएसएमई मंत्रालय के पास संस्तुति के लिए भेजा गया था। प्रायोगिक परियोजना जल्द ही शुरू की जाएगी। इस परियोजना के पूर्ण कार्यान्वयन होने पर अगरबत्ती उद्योग में हजारों की संख्या में रोजगार के अवसर का सृजन होगा। खादी अगरबत्ती 'आत्मनिर्भर मिशन' नाम के इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में बेरोजगारों और प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार पैदा करना और घरेलू अगरबत्ती उत्पादन में पर्याप्त तेजी लाना है।

ग्लेनमार्क ने निम्न से मध्यम स्तर के COVID-19 के मरीज़ों पर

फ़ेवीपीरावीर के फ़ेस-3 नैदानिक परीक्षण के परिणाम घोषित किए

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

ग्लेनमार्क फ़ार्मासिटिकल लिमिटेड ने भारत में सात क्लिनिकल साइट्स पर, निम्न से मध्यम स्तर के COVID -19 के मरीज़ों पर किए गए फ़ेस 3 ट्रायल के टॉप-लाइन परिणामों की घोषणा की है। 150 मरीज़ों पर किए गए इस खुले-लेबल यादृच्छिकृत, बहुकेंद्रीय नैदानिक परीक्षण ने, निम्न से मध्यम स्तर के मरीज़ो में, जिन्हें कि ण्ध्छ्ब्-19 के लिए आरटी-पीसीआर पॉज़ीटिव के परीक्षण के 48 घंटे विंडों के अंतर्गत यादृच्छिकृत किया गया था, मानक सहायक देखभाल मात्र (नियंत्रण शाखा) बनाम मानक सहायक देखभाल (फ़ेवीपीरावीर उपचार शाखा) की प्रभाविकता और सुरक्षा का मूल्यांकन किया है।

फ़ेवीपीरावीर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी वायरस ड्रग है जो चुनिंदा तौर पर RNA-निर्भर RNA पॉलीमर्स (RdRp) और SARS-CoV-2 के वायरल प्रतिकृति चरण को रोकता है, और इसका अध्ययन वर्तमान में हो रहे कई अंतर्राष्ट्रीय नैदानिक परीक्षणों में किया जा रहा है। ग्लेनमार्क फ़ेवीपीरावीर नैदानिक परीक्षण में शामिल मरीज़ों को फ़ेवीपीरावीर टैबलेट 3,600 mg (1,800 mg BID) (efove 1) + 1,600 mg (800 mg BID) (दिन 2 या बाद में) मानक सहायक उपचार के साथ अधिकतम 14 दिनों के लिए दी गई। यादृच्छिकता को निम्न स्तर (90 मरीज़ों) और मध्यम स्तर (60 मरीज़ों) में बिमारी की गंभीरता के आधार पर स्तरीकृत किया गया था। ग्लेनमार्क आने वाले सप्ताहों में साथियों द्वारा समीक्षा किए गए जर्नल में नैदानिक डेटा को प्रकाशन के लिए सबमिट करने और अपने परिणामों को साझा करने की योजना बनाता है। इस अध्ययन के प्रमुख निरीक्षणकर्ताओं में से एक डॉ. ज़ाहिर उद्वाड़िया ने टिप्पणी करते हुए कहा: 'भारतीय फ़ेवीपीरावीर अध्ययन के परिणाम प्रोत्साहनदायी हैं। इस परीक्षण को महामारी की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तत्काल रूप से किया गया था, साथ ही वैज्ञानिक सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। मुझे प्रारंभिक परिणामों को स्वतंत्र रूप से देखने का मौका मिला है और वे प्रोत्साहित कर रहे हैं: फ़ेवीपीरावीर में यादृच्छित किए गए मरीज़ों में तेज़ी से नैदानिक उपचार दिखाई दिया है, और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह कि, रूटीन देखभाल समूह में यादृच्छित मरीज़ों की तुलना में इनमें तेज़ी से वायरल क्लीयरेंस को देखा गया।

ग्लोबल स्पेशलिटी/ब्रांडेड पोर्टफ़ोलियों की वाइस प्रेसिडेंट और हेड डॉ. मोनिका टंडन ने कहा: 'हम टॉप-लाइन परिणामों से प्रोत्साहित है और ये दर्शाते हैं कि निम्न से मध्यम स्तर के मरीज़ों में फ़ेवीपीरावीर के शुरूआती उपचार से नैदानिक परिणामों में सुधार हो सकता है और इससे मरीज़ों की ARDS और मृत्युदर की ओर बढ़ने से संभावित रूप से रोकथाम हो सकती है।'

IRDA का निर्देश

खत्म हो TPA का काम, ताकि ग्राहकों को जल्दी मिले स्वास्थ्य बीमा क्लेम

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

बीमा नियामक इरडा (IRDA) ने थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन (TPA) को बीमा कंपनियों की ओर से स्वास्थ्य बीमा दावों के पेमेंट के फैसले नहीं लेने का निर्देश दिया है। यानी अब दावे के पेमेंट के लिए ग्राहकों और बीमा कंपनियों के बीच कोई नहीं आएगा।

क्या है टीपीए?

थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर बीमा देने वाली कंपनी और बीमा लेने वाले ग्राहकों के बीच एक मध्यस्थ के रूप में काम करता है। इरडा ने कहा है कि दावों की प्रक्रिया में थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ दावों के प्रोसेसिंग के लिए ही शामिल किया जाए। मालूम हो कि जब भी ग्राहक स्वास्थ्य बीमा क्लेम फाइल करते हैं, तो वे टीपीए से संपर्क करते हैं, जो एक बाहरी बिचौलिया होता है और दावों के लिए जनरल बीमा कंपनियों के साथ काम करता है।

पेमेंट में देरी की शिकायतें

बीते कुछ दिनों में कोरोना वायरस महामारी के चलते लोगों में स्वास्थ्य बीमा खरीदने की रुचि बढ़ी है। ग्राहकों को सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कोरोना कवच बीमा भी पेश की गई। इस बीच दावों में भी बढ़ोतरी हुई है और पेमेंट में देरी की शिकायतें आईं हैं।

इन कंपनियों के पास है इन-हाउस क्लेम प्रोसेसिंग टीम

इसलिए अब जनरल बीमा कंपनियों ने इंटरनल टीम बनाकर जल्दी पेमेंट सुनिश्चित करने का काम शुरू किया है। अभी एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, मैक्स बूपा और लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस के पास इन-हाउस क्लेम प्रोसेसिंग टीम है। टीपीए का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जब दावों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हो जाए, तो उस स्थिति में प्रोसेसिंग बाहरी पार्टी द्वारा मैनेज की जाए, जो ग्राहकों के क्लेम प्रोसेस के बारे में सही मार्गदर्शन दे सके। दावों के निपटान की सीमा बढ़ने की वजह से इन-हाउस टीम का बोझ बढ़ा है। प्रयास किए जा रहे हैं कि टीपीए पर निर्भरता कम की जाए और इन हाउस टीमों का निर्माण कर स्वास्थ्य बीमा दावों को निपटाया जाए।

आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करेंगे काशी के कुम्हार

डिजाइनर सामान चीन को देंगे मात

वाराणसी। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार अब चीन को मात दें रहे है। डिजाइनर दीये, झालर, लैम्प के अलावा फ्लॉवर पॉट के साथ घरेलू सजावट के सामानों को अब कुम्हार अपने हाथों से तैयार कर रहे हैं। कुम्हारों के बने ये देशी सामान जल्द ही भारतीय बाजारों में धूम मचाएंगे और भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। वाराणसी खादी ग्रामोद्योग विभाग इसके लिए कुम्हारों को बाकायदा ट्रेनिंग दे रहा है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वाराणसी में अब तक 200 कुम्हारों को हाइटेक बनाने के उद्देश्य से ट्रेनिंग दी गई है। 80 कुम्हारों को जून के महीने में ट्रेनिंग दी गई थी जबकि दूसरा ट्रेनिंग कैंप अभी चल रहा है जिसमें 120 कुम्हार शामिल हैं। इन कुम्हारों को डिजाइनर लैंप, दीये, झूमर और घर के सजावटी सामान कैसे तैयार किए जाएं इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। कुम्हारों के बनाए डिजाइनर प्रोडक्ट जल्द ही बाजारों में नजर आएंगे। भारत में त्योहारी सीजन में चीनी सामानों की बिक्री बढ़ जाती है लेकिन इस बार बाजार में चाइनीज सामानों के बजाय भारत के बने सामान नजर आएंगे। मिट्टी के बने डिजाइनर फ्लावर पॉट, डिजाइनर लैम्प, झूमर और डिजाइनर दीये के साथ घरेलू सजावट के सामानों की बड़ी रेंज बाजार में उपलब्ध होगी।

फॉर्च्यून ग्लोबल ने जारी की लिस्ट

विश्व की टॉप 100 कंपनियों में शामिल हुई रिलायंस

नई दिल्ली। एजेंसी

अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज 10 स्थानों की छलांग लगाकर 'फॉर्च्यून ग्लोबल 500' सूची की शीर्ष 100 कंपनियों में शामिल हो गई है। तेल, पेट्रोरसायन, रिटेल और दूरसंचार जैसे क्षेत्र में काम करने वाली रिलायंस को फॉर्च्यून की वैश्विक कंपनियों की सूची में 96वां स्थान मिला है।

ऐसा करने वाली इकलौती भारतीय कंपनी

फॉर्च्यून की शीर्ष 100 की सूची में शामिल होने वाली रिलायंस इकलौती भारतीय कंपनी है। इससे पहले रिलायंस इस सूची में 2012 में 99वें स्थान पर रही थी, लेकिन बाद के वर्षों में फिसलते हुए 2016 में 215वें स्थान पर पहुंच गयी थी। हालांकि उसके बाद से लगातार रिलायंस की रैंकिंग में सुधार हुआ है।

ये भारतीय कंपनी भी है टॉप 500 में शामिल

'फॉर्च्यून ग्लोबल 500' में 34 अंक फिसलकर सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 151वें स्थान पर रही। वहीं तेल एवं प्राकृतिक गैर निगम (ओएनजीसी) की रैंकिंग पिछले साल के मुकाबले 30 स्थान खिसकर 190वीं रही। देश के सबसे बड़े बैंक, भारतीय स्टेट बैंक की रैंकिंग में 15 का सुधार हुआ और यह 221वें स्थान पर रहा। इस सूची में शामिल होने वाली अन्य भारतीय कंपनियों में भारत पेट्रोलियम 309वीं, टाटा मोटर्स 337वीं और राजेश एक्सपोर्ट्स 462वीं रैंक पर रहीं।

ऐसे बनाई जाती है सूची

'फॉर्च्यून ग्लोबल 500' फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में कंपनियों को उनके पिछले वित्त वर्ष की कुल आय के आधार पर शामिल किया जाता है। भारत की स्थिति में कंपनियों को 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के परिणामों के आधार पर इस सूची में शामिल किया गया है।

वालमार्ट रही टॉप पर

'फॉर्च्यून ग्लोबल 500' में इस साल शीर्ष पर वालमार्ट रही। इसके बाद तीन चीनी कंपनियों साइनोपेक समूह, स्टेट ग्रिड और चाइना नेशनल पेट्रोलियम का स्थान रहा। सूची में पांचवे स्थान पर रॉयल डच शेल और छठे पर सऊदी अरब की प्रमुख तेल कंपनी अरामको रही। सूची में वालमार्ट, साइनोपेक और चाइना नेशनल पेट्रोलियम के स्थान में कोई बदलाव नहीं हुआ। जबकि स्टेट ग्रिड ने दो स्थान की बढ़त हासिल की और शेल दो स्थान नीचे खिसक गयी।

आसुस ने नये और अल्ट्रापोर्टेबल ज़ेनबुक व वीवोबुक लॉन्च किए

10वीं जेनरेशन वाले इंटेलरु कोररू प्रोसेसर के साथ

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

प्रमुख ताइवानी टेक पीसी कंपनी, आसुस, ने आज अपने इनावेटिव और स्टाइलिश ज़ेनबुकऔर वीवोबुक फैमिली में 4 नये उत्पा द शामिल करने की घोषणा की: ज़ेनबुक13/14 (UX325 / UX425), वीवोबुक ए 14 (ए433) और वीवोबुक अल्ट्राव K14 (K413))। कंज्यू मर नोटबुक सेक्श न में अपनी 15% बाजार हिस्सेदारी बढ़ाते हुए, आसुस इंडिया 10वीं जेनेरेशन के इंटेलरु कोररू मोबाइल प्रोसेसर द्वारा संचालित उत्पा दों को लॉन्च किया है।

लॉन्च के बारे में बताते हुए, अर्नोल्ड सु, बिजनेस हेड, कंज्यूमर एंड गेमिंग पीसी, सिस्टम बिजनेस ग्रुप, आसुस इंडिया ने कहा कि 'कंज्यूजमर लैपटॉप सेक्शएन एक नये दौर से गुजर रहा है, विशेष रूप से इस वर्तमान स्थिति में, जहां प्रौद्योगिकी आपस में अधिक तेजी से जुड़ती चली जा रही हैं। बेजोड़ पोर्टेबिलिटी के साथ पावर-पैक परफॉरमेंस निश्चित रूप से लोगों को बेहद आकर्षित करेगा। हमारा मानना है कि ये नई पेशकश अपने अनूठे डिजाइन और रंगों से देश भर में लोगों के दिलों को जीतने के लिए तैयार हैं।'

राहुल मल्होत्रा, डायरेक्टर-रिटेल, इंटेल इंडिया ने कहा कि 'इंटेल का अत्यधिक इंटीग्रेटेड 10वीं जेनेरेशन का इंटेलरु कोररू मोबाइल प्रोसेसर उल्लेखनीय रूप से पतले और हल्के लैपटॉप पर अविश्वसनीय तौर पर आकर्षक मनोरंजन प्रदान करता है। इंटेलरु आइरिशरु प्लेस ग्राफिक्स की विशेषता वाले 10वीं जेनेरेशन के इंटेल कोर प्रोसेसर से संचालित ये लैपटॉप सिस्टम गेमिंग, स्ट्रीमिंग और रचनात्मक कामों के लिए व्यापक सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे अत्यधिक पोर्टेबल उपकरणों पर आरामदेह और स्पटष्ट अनुभव मिलता है। 10वीं जेनेरेशन इंटेल कोर प्रोसेसर द्वारा संचालित ज़ेनबुकऔर वीवोबुककी नई लाइन आज मोबाइल पीसी प्लेटफार्म में संभव पावर-पैक इनोवेशन के उदाहरण हैं।' इन लैपटॉप के साथ व्यापक कनेक्टिविटी सहज हो जाती है जो यूएसबी-सी, एचडीएमआई और एसडी कार्ड रीडर के साथ आई/ओ सेट है। फिंगरप्रिंट सेंसर यह सुनिश्चित करता है कि जब आप दुनिया से जुड़ते हैं तो आपका निजी डेटा गोपनीय बना रहे। वीवोबुक ए14 में अद्वितीय स्टिकर का एक सेट है जो आपके डिवाइस में आपकी सिग्ने चर स्टाबईल को शामिल करता है।

कोविड-19 के उपचार में टैबलेट के बोझ को कम करने के लिए

ग्लेनमार्क ने उच्च शक्ति (400 मिलीग्राम) का फेबीफ्लू पेश किया

देश की पहली कंपनी है जिसने 400 मिलीग्राम की खुराक के लिए स्वीकृति मिली 200 मिलीग्राम टैबलेट की तुलना में मरीज अब अधिक आराम देने वाली खुराक का विकल्प चुन सकते हैं और आईपीटी नेटवर्क

इंदौर। शोध-केंद्रित, एकीकृत वैश्विक दवा कंपनी, ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स, ने घोषणा की कि वह भारत में हल्के से लेकर मध्यम लक्षणों वाले कोविड-19 के उपचार के लिए 400 मिलीग्राम वाला ओरल एंटीवायरल फेबीफ्लूरु पेश करेगी। टैबलेट की उच्च शक्ति, रोगियों द्वारा प्रति दिन ली जाने वाली गोलियों की संख्या को प्रभावी ढंग से कम करके रोगी के अनुपालन और अनुभव को बेहतर बनाएगी। टैबलेट का अधिक बोझ का संबंध थिरेपी का कम होना है, और यह थिरेपी वायरल सप्रेशन और समग्र उपचार के परिणामों को प्रभावित करती है। इसके अलावा, थिरेपी के अनुकूल होने के लिए डॉक्टरों और मरीजों की मांग रही है कि टैबलेट के बोझ को कम किया जाये। फेबीफ्लूरु की 200 मिलीग्राम की खुराक से मरीजों को पहले दिन 18 गोलियां (सुबह नौ और शाम नौ) लेने की आवश्यकता होती है, इसके बाद प्रत्येक दिन अधिकतम 14 दिनों के लिए 8 टैबलेट दी जाती हैं। नए 400 मिलीग्राम वर्जन के साथ, मरीज अब अधिक आराम से खुराक ले पायेंगे - पहले दिन 9 टैबलेट (सुबह 4.5 और शाम को 4.5 टैबलेट), और उसके बाद दूसरे दिन से दवा के कोर्स के अंत तक दिन में दो बार 2 टैबलेट।

इस विकास के महत्व के बारे में बताते हुए, डॉ. मोनिका टंडन, वाइस प्रेसिडेंट एवं हेड, क्लिपिकल डेवलपमेंट, ग्लोबल स्पेशलिटी / ब्रांडेड पोर्टफोलियो, ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, ने कहा कि 'भारत में फेवीपिरवीर को लॉन्च करने वाली पहली कंपनी होने के नाते, हम कुछ नया करना चाहते हैं और कोविड-19 के रोगियों के लिए नए उपचार की खोज करना जारी रखेंगे। उच्च शक्ति वाले फेबीफ्लूरु को पेश करना, रोगियों के लिए आरामदायक अनुभव सुनिश्चित करने के प्रयासों के अनुरूप है, और उन पर टैबलेट खाने के दैनिक बोझ को कम करता है।' डॉ. मोनिका टंडन ने बताया कि 'फेबीफ्लूरु की 200 मिलीग्राम वाली खुराक, फेविपिरविर के वैश्विक फार्मुलेशन के अनुरूप विकसित की गई, जिसकी शक्ति उसके जैसी ही थी। 400 मिलीग्राम का वर्जन भारत में मरीजों के लिए उपचार के अनुभव को बेहतर बनाने के ग्लेनमार्क के अपने आर एंड डी प्रयासों का नतीजा है।'ग्लेनमार्क भारत में मध्यम लक्षणों वाले अस्पताल में भर्ती वयस्क कोविड-19 के रोगियों में एक कम्बिनेशन चिकित्सा के रूप में दो एंटीवायरल दवाओं फेविपिरविर और उमिफेनोविर की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए एक अन्य चरण 3 नैदानिक परीक्षण भी कर रहा है। कम्बिनेशन स्टडी, जिसे एफएआईटीएच ट्रायल कहा जाता है, भारत में मध्यम लक्षणों वाले अस्पताल में भर्ती कोविड-19 के 158 मरीजों को सूचीबद्ध करना चाहती है।

ऑयल इंडिया लिमिटेड के तेल कुएं में गैस रिसाव होने से कच्चे तेल व गैस का उत्पादन प्रभावित

नई दिल्ली। एजेंसी

ऑयल इंडिया लिमिटेड ने मंगलवार को कहा कि असम के तिनसुकिया जिले के बागजान गैस कुएं में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का संचयी नुकसान क्रमशः 25,624 मीट्रिक टन और 616.2 लाख मानक क्यूबिक मीटर (MMSCM) रहा। बागजान तेल क्षेत्र स्थित ऑयल इंडिया लिमिटेड के एक तेल कुएं में गैस रिसाव हुआ। गैस का रिसाव 27 मई 2020 को शुरू हुआ था। इसने बीते नौ जून को आग पकड़ ली। बागजान ईपीएस से जुड़े कुछ तेल और गैस कुओं के बंद होने के कारण तेल और गैस उत्पादन अभी भी प्रभावित हो रहा है। संचालन बंद होने के कारण कुछ स्थानों पर ड्रिलिंग और कार्यस्थल का संचालन भी प्रभावित हुआ है। ओआईएल ने कहा कि कुएं को बंद करने की तैयारी जारी है। तकनीकी खराबी के कारण सोमवार को आग बुझाने का दूसरा प्रयास विफल हो गया। सार्वजनिक उपक्रम के प्रवक्ता त्रिदिव हजारिका ने बताया कि विशेषज्ञ कुएं के मुंह पर बीओपी रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अत्यधिक गर्मी के कारण केबल टूट गया।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा भारत, देश में बनेंगे 101 उपकरण

नई दिल्ली। एजेंसी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। रक्षा मंत्रालय 101 से ज्यादा वस्तुओं की लिस्ट तैयार की है, जिनके आयात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इस लिस्ट में कुछ उच्च तकनीक वाले हथियार सिस्टम भी शामिल हैं। आयात पर प्रतिबंध को 2020 से 2024 के बीच धीरे-धीरे लागू करने की योजना है। रक्षा मंत्री ने बताया कि रक्षा क्षेत्र में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई इस लिस्ट को सेना, पब्लिक और प्राइवेट इंडस्ट्री से चर्चा के बाद तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि इन 101 वस्तुओं में सिर्फ आसान वस्तुएं ही शामिल नहीं हैं बल्कि कुछ उच्च तकनीक वाले हथियार सिस्टम भी हैं जैसे आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफलें, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, LCHs, रडार और कई अन्य आइटम हैं जो हमारी रक्षा सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए हैं। इन 101 उत्पादों की लिस्ट में आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स भी शामिल हैं। राजनाथ सिंह के मुताबिक, ऐसे उत्पादों की करीब 260 योजनाओं के लिए तीनों सेनाओं ने अप्रैल 2015 से अगस्त 2020 के बीच लगभग साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे। अगले 6 से 7 सालों में घरेलू इंडस्ट्री को लगभग 4 लाख करोड़ रुपये का ऑर्डर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला भारतीय रक्षा उद्योग को अपने स्वयं के डिजाइन और विकास क्षमताओं का उपयोग करके सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अवसर प्रदान करेगा। रक्षा मंत्री ने यह घोषणा ऐसे वक्त की है जब वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। शनिवार को एक बार फिर दोनों देशों के बीच हुई सैन्य स्तरीय वार्ता बेनतीजा रही। जानकारी के मुताबिक मुताबिक देपसांग और पैंगोग त्सो के पास एलएसी को लेकर बना मतभेद बरकरार है। उधर, भारतीय सेना पहले से ही पूरी सतर्कता बरत रही है। समूचे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत सभी रणनीतिक स्थलों पर अपने सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ा रहा है। वायु सेना भी पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि किसी भी स्थिति का सामना किया जा सके।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।